आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 12 अंक : 17 लखनऊ, शनिवार 07 अगस्त से 13 अगस्त, 2021 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' विषय पर संबोधित करते हुए PM मोदी बोले, चार तरीके से बढ़ेगा एक्सपोर्ट

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और देश के व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के हितधारकों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि ये समय आजादी के ७५वें वर्ष में अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाने का तो है ही उसके साथ–साथ भविष्य के भारत के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण और रोडमैप के निर्माण का अवसर भी है। इसमें आप सभी साथियों की भागीदारी, पहल और रोल बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीकी और वित्तीय कनेक्टिविटी की वजह से दुनिया हर रोज और छोटी होती जा रही है। ऐसे में हमारे निर्यात का विस्तार के लिए दुनियाभर में नई संभावनाएं बन रही हैं। ७ साल पहले हम लगभग ८ बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन बाहर से मंगवाते थे। अब यह घटकर २ बिलियन

डलर हो गया है। ७ साल पहले भारत सिर्फ ०.३ बिलियन डलर के मोबाइल का निर्यात करता था जो अब ३ बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। निर्यात बढ़ाने के लिए ४ घटक महत्वपूर्ण हैं– देश में विनिर्माण कई गुणा बढ़े, ट्रांसपोर्ट की लजिस्टिक की समस्या दूर हो, निर्यात के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चले और भारतीय सामान के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के लगभग हर हिस्से के साथ हमारे ट्रेड लिंक रहे हैं और ट्रेड रूट भी रहे हैं। आज जब हम ग्लोबल इकनमी में अपनी उस पुरानी हिस्सेदारी को वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं तब भी हमारे निर्यात की भूमिका अहम है। भारत ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सटेशन से मुक्ति का जो फैसला लिया है, वो हमारा कमिटमेंट दिखाता है, नीतियों में निरंतरता दिखाता है।

प्रदेश भर में ९० फीसदी अभ्यर्थियों ने दी बीएड प्रवेश परीक्षा, दो गिरफ्तार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड–२०२१ शुक्रवार को सम्पन्न हुई। प्रदेश के १४७६ केंद्रों पर कुल पंजीकृत ५,६१,३०५ परीक्षार्थियों में से ५३२०७६ अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए और उपस्थिति ६० प्रतिशत रही। इनमें ५२ नेत्रहीन अभ्यर्थी भी सम्मिलित थे, जिन्हें नियमानुसार परीक्षा केंद्र पर श्रुतलेखक भी उपलब्ध कराया गया। विभिन्न केंद्रों पर कुल ३३ अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिनका तापमान सामान्य से अधिक होने पर आइसोलेटेड कक्ष में बैठाकर परीक्षा दिलाई गई। कोविड–१६ के कारण बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए अभ्यर्थियों, कक्ष निरीक्षकों और नोडल अधिकारियों की सुरक्षा के सभी प्रोटोकाल एवं निर्देशों का कठोरता से पालन कराया गया। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे, राउटर आदि की समुचित व्यवस्था की गई। इनकी रिकार्डिंग का बैकअप लेकर सुरक्षित रख लिया गया है और भविष्य में उपयोग में लाया जा सकेगा। बायोमेट्रिक व तकनीकी की सहायता से प्रथम दृष्टया कुछ संदिग्ध प्रकरण जानकारी में आए हैं जिनकी आवेदन पत्र में अंकित मूल अभ्यर्थी के विवरण से मिलान कर जांच की जा रही है। फेसियल बायोमेट्रिक प्रक्रिया व ओएमआर पर अंकित बारकोड व डेस्क स्लिप को एक साथ किया गया है ताकि किसी भी स्टेज पर ओएमआर उत्तर–पत्रक में कोई बदलाव की संभावना न रहे। प्रदेश के सभी केंद्रों की परीक्षा पर लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित कमांड नियंत्रण कक्ष से कड़ी नजर रखी गई। कोरोना वायरस से सुरक्षा व बचाव के लिए कुल ६.२५ लाख कोरोना सुरक्षा किट दी गई। जिसमे फेस शील्ड एक, फेस–मास्क दो, सैनिटाइजर पाउच चार, डिस्पोजेबल स्ट्रिप एक, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को दूसरे की स्पर्श की गई स्ट्रिप न छूना पड़े, कैरी बैग आदि उपयोगी वस्तुएं परीक्षा केंद्र पर दी गई। प्रथम पाली में प्रतापगढ़ उपनोडल केंद्र पर और दूसरी पाली में शामली उप नोडल केंद्र पर एक–एक महिला अभ्यर्थी द्वारा फर्जी प्रवेश पत्र की सहायता से परीक्षा में सम्मिलित होने की कोशिश की गई। संबंधित स्थानीय अधिकारियों ने यह सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय भेजी। इस पर तत्काल डाटा से मिलान करने पर यह प्रवेश पत्र फर्जी पाया गया। प्रयागराज उप नोडल शहर के तहत दो अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते पकड़े गए। एसटीएफ ने बीएड प्रवेश परीक्षा में साल्वर गैंग का खुलासा किया है। इस मामले में अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रही एक युवती और एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ का दावा है कि युवती अभी तक विभिन्न अभ्यथियों के स्थान पर पांच प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ चुकी है। इसके लिए युवती बकायदा मोटी धनराशि वसूल करती थी।

उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के केवल 41 नये मामले आये

लखनऊ। गत एक दिन में कुल २,५०,०३६ सैम्पल की जांच की गयी। अब तक कुल ६,६६,६७,७८३ सैम्पल की जांच की गयी। पिछले २४ घंटे में कोरोना संक्रमण के ४१ नये मामले आये। विगत २४ घंटे में ७६ लोग तथा अब तक कुल १६,८५,२६६ लोग कोविड–१६ से ठीक हुये। कोविड–१६ से ठीक होने वालों का ९८.६ प्रतिशत प्रदेश में कोरोना के कुल ६१६ एक्टिव मामले। प्रदेश में विगत ०५ अगस्त को ६,६३,१६३ लोगों को वैक्सीन की डोज दी गयी। पहली डोज ४,४६,०६,८०२ व दूसरी डोज ८२,४२,२०५ तथा अब तक कुल ५,२८,४६,००७ डोजें लगायी गयी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि गत एक दिन में कुल २,५०,०३६ सैम्पल की जांच की गयी है। प्रदेश में अब तक कुल ६,६६,६७,७८३ सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले २४ घंटे में कोरोना संक्रमण के ४१ नये मामले आये हैं। प्रदेश में विगत २४ घंटे में ७६ लोग तथा अब तक कुल १६,८५,२६६ लोग कोविड–१६ से ठीक हो चुके हैं। कोविड–१६ से ठीक होने वालों का प्रतिशत ९८.६ प्रतिशत है। प्रदेश में कोरोना के कुल ६१६ एक्टिव मामले हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विगत ०५ अगस्त को ६,६३,१६३ लोगों को वैक्सीन की डोज दी गयी है। पहली डोज ४,४६,०६,८०२ लोगों को तथा दूसरी डोज ८२,४२,२०५ लोगों को तथा अब तक कुल ५,२८,४६,००७ डोजें लगायी गयी हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निशुल्क किताबों के वितरण में विभाग की लापरवाही

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक जूनियर विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाने वाली निशुल्क किताबों के वितरण में लापरवाही की जा रही है। ये शिकायत करीब ४० जिलो में हैं। इस संबंध में कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पाठ्य पुस्तक अधिकारी श्याम किशोर तिवारी ने लापरवाही की वजह भी पूछी है। साथ ही दिशा निर्देश दिया भी दिया गया है कि किताबों का वितरण शुरू कराया जा ताकि बच्चों को समय से किताबें मिल सके और घर पर रहकर पढ़ाई भी कर सकेंगे। दरअसल मौजूदा समय में कोरोना काल में बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा रहा है, ऐसे में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पर ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल व इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि बच्चों तक समय से किताबे पहुंच जायें यही बेहतर विकल्प है। बेसिक शिक्षा विभाग अब तक ६५ प्रतिशत किताबों का मुद्रण करा कर जिलों में भेज चुका हैं। जिलों से यह किताबें छात्रों को वितरित की जा रही हैं। पाठ्य पुस्तक अधिकारी श्याम किशोर तिवारी के मुताबिक दस दिन में शेष पुस्तकों को प्रिंट करा लिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक व उच्च प्राथमिक, राजकीय एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले कक्षा १ से ८ तक के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों व कार्य पुस्तिकाओं का वितरण कराता है। पिछले सत्र में परिषदीय विद्यालयों के १,८३,७२६३२ छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ कार्य पुस्तिकाएं वितरित की गई थीं जबकि वर्तमान २०२१–२२ में १ करोड़ ८५ लाख से अधिक छात्रों को पुस्तकों का वितरण किया जाना है। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि पुस्ध्तकों के मुद्रण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कक्षा एक से आठ तक के छात्रों की ६५ प्रतिशत किताबों को मुद्रण पूरा हो चुका है। शेष ३५ प्रतिशत किताबों का मुद्रण अगस्त के दूसरे सप्ताह तक पूरा हो जाएगा। किताबों को जिलों में भेजने का काम भी तेजी से किया जा रहा है ताकि जिलों से छात्रों तक किताबें जल्दी पहुंच सके।

सम्पादकीय

देश में महिलाओं की स्थिति लगातार खराब

लैंगिक समता की कसौटी पर भारत की स्थिति पहले भी बेहतर नहीं थी। लेकिन अब बने देश में माहौल और कोरोना महामारी के प्रभाव ने हालत और बिगाड़ दी है। इस बात की तरफ पहले भी ध्यान खींचा गया है। लेकिन हाल में आई २०२१ की वर्ल्ड इकनमिक फोरम की 'ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स' रिपोर्ट ने बताया है कि हाल कितनी तेजी से बिगड़ रहा है। फोरम के इस इंडेक्स में १५६ देशों के बीच भारत अब नीचे १७वें स्थान पर है। मतलब साफ है। देश में महिलाओं की स्थिति लगातार खराब हो रही है। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई महिला मंत्री शामिल हुईं। इसके बावजूद महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक बना हुआ है। भारत से खराब स्थिति सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। जबकि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान सभी भारत से आगे निकल चुके हैं। महिलाओं के राजनीतिक रूप से सशक्त होने के मामले में भारत का रैंक इस साल ५१ हो गया है। यह पिछले साल १८ था। इसका मतलब है कि जो भी कानून बनाए जाते हैं, उनके लिए होने वाली चर्चा में महिलाओं का पक्ष और उनके हित ठीक नहीं झलक पाते। मसलन जनसंख्या नियंत्रण कानून को लें। जनसंख्या नियंत्रण कानून असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तैयार किया जा चुका है, जबकि कई अन्य भाजपा शासित राज्य ऐसे कानून बनाने की अभी तैयारी कर रहे हैं। इस कानून में दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर चुनाव लड़ने से रोक और सरकारी सब्सिडी खत्म किए जाने का प्रावधान है। इस कानून से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं होंगी। जाहिर है, महिलाओं का बिना हित जाने पुरुषवादी सोच के तहत ऐसे कानून समाज पर थोपे जा रहे हैं। ये गौरतलब है कि ज्यादातर राज्यों में कुल मतदाताओं की करीब ५० प्रतिशत महिलाएं हैं। लेकिन इन चुनावों में महिला उम्मीदवार मात्र १० फीसदी रही हैं। हाल के हुए विधानसभा चुनावों में केरल में ६ फीसदी और असम में ७.८ फीसदी महिलाएं ही उम्मीदवार थीं। तमिलनाडु, पुडुचेरी में करीब ११ फीसदी उम्मीदवार महिलाएं रहीं। बहरहाल, महिलाओं की जितनी कमजोर स्थिति राजनीति में है, उससे कहीं ज्यादा आम परिवारों के भीतर है। ये सूरत बीते दशकों में थोड़ी बदल रही थी। लेकिन अब बाजार के बिगड़ते हाल ने महिलाओं को फिर से घरों के अंदर बैठने और पुरुषवादी पारिवारिक व्यवस्था के दायित्वों को निभाने के लिए मजबूर कर दिया है।

जलशक्ति मंत्री ने जल जीवन मिशन के लिए बड़ी धनराशि जारी करने पर प्रधान मंत्री एवं केन्द्रीय जल मंत्री जी का जताया आभार

लखनऊ। केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 'हर घर जल' परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२१–२२ हेतु प्रथम किस्त के रूप में २३६८.६१ करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी कर दी है। यह जानकारी उ०प्र० के जल शक्ति मंत्रीध्नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति मंत्री डा० महेन्द्र सिंह ने दी है। जल शक्ति मंत्री ने इतनी बड़ी ध नराशि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जारी करने के लिए मा० प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत व मा० मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु केन्द्र सहायतित जल जीवन मिशन का संचालन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा ५०–५० प्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर किया जा रहा है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से ''हर घर जल'' उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष २०२१–२२ में केन्द्रांश में कुल आवंटित ध नराशि रू० १०८७०.५० करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के प्रथम अंश की धनराशि रू० २३६८.६२ करोड़ अवमुक्त कर दी गई है। इस राशि के जारी होने से नमामि गंगे परियोजनाओं के कार्यो में तेजी आयेगी व परियोजनाओं को समयबद्धता के साथ पूर्ण होने में सहायता मिलेगी। डा० महेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में योगी जी के कुशल नेतृत्व एवं प्रेरणा से ''हर घर जल'' उपलब्ध कराने की योजना पर तेजी से कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि शीघ्र ही पेयजल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में आम जनमानस को शुद्ध पेय जल की आपूर्ति सम्भव होगी।

आइटी सेल की कार्यशाला में सीएम योगी बने डिजिटल गुरु, कहा–भाषा की मर्यादा बनाए रखें

लखनऊ। धर्मक्षेत्र से राजनीति में धाक जमाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को डिजिटल गुरु सरीखे दिखे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश भर से आए आईटी व सोशल मीडिया विभाग के क्षेत्रीय व जिला संयोजकों को उन्होंने बड़ी बारीकी से प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के टिप्स दिए। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, जहां प्रशिक्षण की जरूरत है। इसलिए भाजपा कार्यकर्ता भाषा की मर्यादा बनाए रखें। सोशल मीडिया व आइटी विभाग की कार्यशाला करके भाजपा ने एक तरह से शुक्रवार को चुनावी बिगुल फूंक दिया। जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटी सेल और सोशल मीडिया की अलग–अलग भूमिका को रेखांकित किया। फिर कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार के इतने सारे सकारात्मक कार्य व उनके डेटा हैं। जिनका व्यापक तौर पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्वीटर व टेलीग्राम पर प्रचार करना चाहिए। यह डेटा राइटिंग कंटेंट की बजाय मल्टीमीडिया फ्रेम में मसलन कार्टून, इंफोग्राफिक्स, कंपरेटिव चार्ट आदि से प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया बेहद महत्वपूर्ण है और मीडिया भी यहां से मुद्दे उठाता है। पेगासस मामले को लेकर संसद में हुए हंगामे पर उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि इसमें कोई तथ्य या प्रमाण नहीं है। उन्होंने ऐसे विषयों पर सावधान रहने का सुझाव दिया। इस दौरान सीएम ने धारा ३७० से लेकर बिना विवाद के राममंदिर निर्माण का फैसला

आने, निर्माण शुरू होने और कोरोना काल में हुए कार्यों की भी जानकारी दी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा, आइटी व सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष अंकित सिंह चंदेल और राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र व राज्य सरकार आवास, जनधन, गरीब कल्याण, कोराना काल की सेवाओं आदि के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे लाभार्थियों के जीवन में बदलाव आए हैं। हरेक कार्यकर्ता दस लाभार्थियों का २०–२० सेकेंड का वीडियो बनाकर यह बदलाव सोशल मीडिया पर अपलोड करे। समापन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आपके दम पर २०२२ चुनाव जीतना है। सोचो तो ठंडा सोचो, मीठा बोलो, सीने में आग, और पैर में चक्कर। जब तक बूथ तक समिति और व्हाट्सएप ग्रुप न बन जाए तब तक चलते रहना है। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने संयोजकों को २५ सितंबर तक सेक्टर व बूथ स्तर तक यह तैयारी करने को कहा। कहा कि अब आईटी विभाग कल सेंटर, मैसेजिंग, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन, कार्यकर्ताओं से डिजीटल कम्यूनिकेशन और वर्चुअल मीटिंगें आयोजित कराएगा। जबकि सोशल मीडिया विभाग केवल सोशल मीडिया का दायित्व संभालेगा।

सोशल मीडिया पर विपक्ष के मुद्दे हावी, भाजपा का रिस्पांस लेट, भगवा खेमा चिंतित

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी व सोशल मीडिया विभाग में साढ़े दस हजार कार्यकर्ता हैं। बावजूद इसके पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों के मुद्दे सोशल मीडिया पर जल्दी छा जाते हैं, उन पर प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और भाजपा की ओर से जवाब आने में देरी लग जाती है। पेगासस से लेकर हालिया समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। भारी भरकम डिजीटल फौज के बावजूद इस हालात से भगवा खेमा चिंतित है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के संबोधन में यह चिंता स्पष्ट नजर आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि इतने सारे कार्यकर्ताओं के होते हुए भी हमारा रिस्पांस लेट हो जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से तत्काल डेटा

डिलीवरी करने और मजबूत तर्क व डेटा के साथ अपनी बात रखने के लिए कहा। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने भी इस विषय में अपनी चिंता जताई। शायद यही वजह है कि इतने सारे समर्पित कार्यकर्ताओं के बावजूद अब पार्टी सोशल वालंटियर भी बनाए जा रही है। कार्यशाला में इस संबंध में भी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। कहा गया कि समान विचारध ारा रखने वाले वह लोग जो भले ही पार्टी के कार्यकर्ता न हों, उन्हें सोशल मीडिया वालंटियर बनाया जाए। जो पार्टी की रीति नीति के अलावा सरकार का पक्ष कुशलता से रख सकें। ऐसे वालंटियर यदि १८ वर्ष से कम हों तो भी उन्हें साथ लिया जा सकता है। कार्यशाला में संयोजकों ने प्रदेश स्तर से कंटेंट उपलब्ध कराने की भी मांग की।

छात्रवृत्ति वितरण योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 800 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान

लखनऊ। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति वितरण योजना के अन्तर्गत पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने के लिए छात्रवृत्ति को पूर्णतया कम्प्यूटरीत किया गया है। इस संबंध ा में समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने बताया कि छात्र द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने और आधार प्रमाणीकरण की अनिवार्य व्यवस्था लागू की गई है। श्री शास्त्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष २०२०–२१ में कुल ३६२५११ छात्रों को लाभान्वित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए ८०० करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य का अंश ४० प्रतिशत निर्धारित है। भारत सरकार के नवीन नियमावली व निर्देशों के अनुसार ६० प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार द्वारा सीधे छात्र–छात्राओं के खाते में अन्तरित की जाती है।

प्रदेश की बेटियों के लिए इस बार का रक्षाबंधन पर्व बेहद खास

लखनऊ। प्रदेश की बेटियों के लिए इस बार का रक्षाबंधन पर्व बेहद खास होने वाला है। पर्व से एक दिन पूर्व २१ अगस्त को "मिशन शक्ति ३.० की शुरुआत होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री महिलाओं–बेटियों को कई बड़े तोहफे देने की तैयारी में हैं। सबसे ज्यादा तोहफे महिला पुलिसकर्मियों के लिए होंगे। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला पुलिसकर्मियों को पुरुष सहकर्मियों की तरह ही "बीट पुलिस अधिकारी" के रूप में तैनाती का उपहार देंगे। महिला पुलिसकर्मियों के नन्हें–मुन्ने बच्चों के लिए सभी ७८ पुलिस जनपदों में "बालवाड़ी" का उपहार भी मुमख्यमंत्री देंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने 'मिशन शक्ति' के तीसरे चरण के तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मुख्य समारोह की तर्ज पर शेष ७४ जिलों में भी विशेष आयोजन कराने के निर्देश दिए। जिलों में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों या विधाओं में नाम कमा चुकी प्रसिद्ध महिलाएं ही मंचासीन होंगी। मुख्य समारोह में ओलम्पिक प्रतिभागी बेटियों की खास मौजूदगी हो सकती हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से वंचित १.५ लाख बेटियों को और निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्र १.७३ लाख नई लाभार्थी महिलाओं को योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्य समारोह और जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में कोविड काल में उत्ष्ेट कार्य करने वाली महिला चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा, करीब १३०० थानों में पिंक टयलेट निर्माण, नवनिर्मित ग्राम सचिवालयों में 'मिशन शक्ति हेल्पडेस्क', महिला पुलिसकर्मियों के खाली पदों पर भर्ती जैसी उपहार मिलने की भी संभावना है। कार्यक्रम में करीब एक करोड़ महिलाओं–बेटियों की सहभागिता कराने की तैयारी है। योगी सरकार की ओर से सभी को एक–एक "मास्क और राखी" का सुरक्षा कवर भी प्रदान किया जाएगा मिशन शक्ति का तीसरा चरण कई मायनों में खास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक के दो चरण में महिला सुरक्षा

सुनिश्चित करने और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिहाज से उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अब नए चरण में इन दो विषयों के साथ स्वावलंबन पर फोकस करना होगा। महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने सोनभद्र, चंदौली, मीरजापुर, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और रामपुर जिलों में भी झांसी की बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की तर्ज पर उत्पादक इकाइयों के गठन के निर्देश दिए हैं। यही नहीं दिसंबर तक १ लाख नई स्वयं सहायता समूहों के गठन का भी लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत ग्रामीण अंचलों में खेतिहर श्रमिक, पशुपालक, ईंट–भट्ठों पर काम करने वाली महिलाओं, स्कूल ड्रॉपआउट बेटियों पर ध्यान केन्द्रित करके शक्ति मोबाइल द्वारा जागरूकता व प्रवर्तन का अभियान चलाने की जरूरत भी बताई। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास, माध्यमिक, बेसिक व उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, युवा कल्याण सहित सभी संबंधित विभागों को मिशन शक्ति के नए चरण के दौरान महिला हित से जुड़ीं सरकार की योजनाओं से महिलाओं को लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला से जुड़े अपराध हो अथवा उनकी कोई अन्य समस्या, सभी कार्यालय इनका समाधान शीर्ष प्राथमिकता के साथ करना सुनिश्चित करें। ग्राम विकास विभाग की कार्ययोजना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन ग्राम सचिवालय को ग्राम पंचायतों को एक व्यवस्थित स्वरूप देने वाला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में सामुदायिक शौचालय, बीसी सखी जैसे प्रयास महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। सीएम ने अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग को महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की जांच के विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए तो शिक्षा विभाग को लैंगिक संवेदनशीलता, अभिभावकों में जागरूकता, किशोरी बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने जैसे प्रयास करने पर भी जोर दिया।

अवैध रूप से म्यांमार व बांग्लादेशियों को बसाने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार

लखनऊ। फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में बसने का खेल खेलने वाले एक और शातिर को यूपी एसटीएस ने हैदराबाद तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। यह मूलरूप से म्यांमार का रहने वाला है और उसका नाम मो. इस्लाम है। इस मामले में अभी तक कुल पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य सरगना नूरुल इस्लाम उर्फ मोहम्मद नूर को यूपी एटीएस ने २७ जुलाई को ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस से गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। इसकी निशानदेही पर ही एटीएस ने छापेमारी कर बीते दिनों ही बरेली की मारिया मीट फैक्ट्री से दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। यह दोनों कूटरचित दस्तावेज बनवाकर भारतीय नागरिक बन गए थे और फैक्ट्री में काम करने लगे थे। मोहम्मद नूर की ही निशानदेही पर एटीएस ने गुरुवार को हैदराबाद से मो. इस्लाम की गिरफ्तारी की है। हैदराबाद से ट्रांजिट रिमांड लेकर टीम लखनऊ पहुंच चुकी है। यहां न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर एटीएस उसकी रिमांड लेकर उससे पूछताछ कर रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले में देश में फर्जी दस्तावेजों के जरिए रह रहे कई और बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों की गिरफ्तारी हो सकती है। यूपी एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि ऐसी जानकारी मिली थी कि मानव तस्कर गैंग का सदस्य हैदराबाद में अपना सिंडिकेट फैला रहा है। इस सूचना पर यूपी एटीएस की टीम ने हैदराबाद के बहादुरपुरा थानाक्षेत्र के प्रिंस कलोनी में छापा मारकर आरोपी मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार किया है। एटीएस द्वारा अभी तक गिरफ्तार किए गए सभी नागरिक म्यांमार व बांग्लादेश के निवासी हैं। फर्जी तरीके से भारत में बसाने के मामले में इस गिरोह के जिन सदस्यों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है उनमें मोहम्मद नूर उर्फ नुरुल इस्लाम, रहमतुल्लाह, शफीउल्लाह और १८ जून को मुजम्मिल, अतीकुर्रहमान शामिल हैं। फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में बसाने का खेल खेलने वाले गिरोह के सदस्य इस बावत मोटी रकम वसूलते हैं। विशेषकर महिला व बच्चों को भारत में अच्छा जीवन जीने, अच्छे परिवार में शादी कराने, फैक्ट्री व अन्य स्थानों पर काम दिलाने का झांसा देते हैं। इसके बाद अवैध तरीके से बार्डर पार कराने और भारत में निवास के बावत जरूरी दस्तावेजों को फर्जी तरीके से बनाने के लिए भी मोटी रकम वसूलते हैं। म्यांमार व बांग्लादेश की सीमा पार कर भारत में प्रवेश करने के बाद यह लोग अपने संपर्कों के माध्यम से विशेषकर दिल्ली, एनसीआर क्षेत्रों में बसा देते हैं। एटीएस सूत्रों की मानें तो गिरोह के सदस्यों से अभी पूछताछ जारी है। उम्मीद है कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिए भारत में रह रहे कई और बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों की गिरफ्तारी होगी।

४०० का सपना देख रहे सपा नेता के सामने चुनाव में ४० सीटें बचाने की बड़ी चुनौती : सिद्धार्थ नाथ सिंह

लखनऊ। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ४०० का सपना देख रहे सपा नेता के सामने चुनाव में ४० सीटें

बचाने की बड़ी चुनौती है। सिंह ने कहा कि गुंडों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का गैंग चलाने वाले अखिलेश यादव के मुंह से कानून–व्यवस्था और न्याय की बात अच्छी नहीं लगती। डेढ़ साल बाद घर से बाहर निकले अखिलेश भ्रमित और घबराए हुए हैं। ४०० का सपना देख रहे सपा नेता के सामने चुनाव में ४० सीटें बचाने की बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल बाद जनता की सुध लेने वाले अखिलेश घबराहट में हैं। डेढ़ साल तक घर में बैठ कर ट्विटर से राजनीति चलाने वाले अखिलेश जमीनी हकीकत से सामना नहीं कर पा रहे हैं। अपराधी और माफिया सहयोगियों के सफाए से सपा और अखिलेश अकेले और परेशान हैं। सिंह ने कहा कि किसानों को तबाह करने वाले अखिलेश को किसानों की खुशहाली और ृषि विकास को देखना चाहिए। योगी सरकार ने चार साल में किसान, नौजवान, मजदूरों और ग्रामीणों की किस्मत बदलने का काम किया है। जिन गन्ना किसानों का पैसा अखिलेश सरकार नहीं दे पाई थी, वह भी योगी सरकार ने किसानों को दिया है।

सरकार को क्यों नहीं दिखता ये अंधेरा, हादसे व अपराध का डर

लखनऊ। यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ है के ऊपर से गुजरती मेट्रो के नीचे साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें दिन में बड़ा सुकूनदायक अहसास कराती हैं, लेकिन रात ढलते ही यहां अंधेरा छा जाता है। क्योंकि नगर निगम ने यहां स्ट्रीट लाइटें ही नहीं लगाई हैं। क्योंकि स्ट्रीट लाइटों के लग जाने से यहां लगे विज्ञापन के होर्डिंगों की चमक फीकी पड़ जाएगी। कंपनियों को यह फायदा पहुंचाते समय अफसर भूल गए कि इस अंधेरे का फायदा असामाजिक तत्व भी उठा सकते हैं और इससे हादसों का भी खतरा है। शहर में वैसे तो सड़कों पर नगर निगम की स्ट्रीट लाइटें शाम ढलते ही चमकना शुरू हो जाती हैं, लेकिन मेट्रो लाइन के नीचे कहीं यह इंतजाम नजर नहीं आता। यहां डिवाइडर पर लगे विज्ञापन के होर्डिंगों से आ रही हल्की रोशनी से ही राहगीरों को काम चलाना पड़ता है। रात आठ बजे लखनऊ विश्वविद्यालय के पास से गुजर रहे त्रिवेणीनगर निवासी त्रिपुरेश शुक्ला कहते हैं कि यहां अंधेरे की वजह से हर वक्त डर सा लगता है। इस बारे में मेट्रो कार्पोरेशन के अफसर साफ हाथ उठा देते हैं। यूपीएमआरसी के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्र कहते हैं कि कार्पोरेशन ने सड़कें बनाने के बाद संबंधित विभागों को हैंडओवर कर दिया है। इसलिए यहां स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की है। स्टेशन के नीचे के हिस्से में कार्पोरेशन ने लाइटें लगवा रखी हैं, जबकि कायदे से यह काम भी इन्हीं सरकारी एजेंसियों को करना चाहिए। शहर की इन्हीं सड़कों से रातदिन प्रदेश के शीर्ष अधिकारी से लेकर नगर विकास मंत्री तक गुजरते हैं, लेकिन किसी को यह अंधेरा जाने क्यों नहीं खटक रहा है। वर्ना राजधानी में यह अंधेरा अब तक कायम नहीं रहता। मेट्रो लाइन के नीचे स्ट्रीट लाइट किसे लगवानी है, फिलहाल यह मेरी जानकारी में नहीं है। यदि नगर निगम को लगवाना होगा तो जल्द ही ये लाइटें लगवा दी जाएंगी–अजय कुमार द्विवेदी, नगर आयुक्त।

उत्तर प्रदेश के विधायी एवं न्याय मंत्री ने 56.62 लाख रुपये की लागत से 11 विकास संबंधी परियोजनाओं का किया लोकार्पण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विधायी एवं न्याय, ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री ब्रजेश पाठक आज अपने मध्य विधानसभा क्षेत्र, लखनऊ राजेन्द्र नगर में ५६.६२ लाख रूपये की लागत से पं० दीन दयाल उपाध्याय द्वार सहित ११ विभिन्न विकास संबंधी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राजेन्द्र नगर के निवासियों की काफी समय से मांग थी कि पं० दीन दयाल उपाध्याय का द्वार बनाया जाए। जो आज बनकर तैयार हो गया है और जनता को समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य विधानसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास के लिए वह सदैव कटिबद्ध हैं। पाठक ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान मध्य विधानसभा क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को दवाईय, राशन, भोजन एवं अन्य सामग्री का वितरण कराया गया। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन अवश्य करायें साथ ही कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा मिल सके। विधायी एवं न्याय मंत्री आज रानीगंज चौराहे के आगे, राजेन्द्र नगर में मध्य विधानसभा क्षेत्र में पूरी हुई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य विधानसभा क्षेत्र की सभी परियोजनाए शीघ्रता से निर्धारित समय पर पूरी हो रही है। समय से पूर्ण होने पर इसका लाभ आम जनमानस को

मिल रहा है। मध्य विधानसभा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मध्य विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं रखूंगा। आम–जनमानस की छोटी–बड़ी समस्या को गम्भीरता से लिया जाएगा तथा इसके निराकरण के लिए हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। पाठक आज राजेन्द्र नगर वार्ड में १६.८४ लाख रूपये की लागत से पं० दीन दयाल उपाध्याय द्वार का निर्माण के अलावा, इसी वार्ड के अन्तर्गत ६.४६ लाख रूपये की लागत से रोजा बाग मोहल्ले में आर०के० अग्रवाल के मकान से रामनारायण प्रजापति के मकान तक एवं कनेक्टेड गलियों का सी०सी० रोड, इसी वार्ड के अन्तर्गत ८.५६ लाख रूपये की लागत से बिरहाना पार्क के तीन तरफ सी०सी० सड़क एवं नाली, तिलकनगर वार्ड के अन्तर्गत ५.२३ लाख रूपये की लागत से कुण्डरी रकाबगंज वार्ड में नारायण प्रेस वाली गली में श्री रजत सिंह चौहान से शुभम रस्तोगी तक सड़क व नाली, इसी वार्ड के अन्तर्गत ६६ हजार रूपये की लागत से तिलक नगर में म०नं० १३ के पास समरसेबिल पम्प बोरिंग व पानी की टंकी लगाने, इसी वार्ड के अन्तर्गत ६६ हजार रूपये की लागत से कुण्डरी रकाबगंज में लोधेश्वर महादेव मंदिर १ श्मशान घाट के पास १ समरसेबिल पम्प बोरिंग व पानी की टंकी लगाने एवं राजा बाजार वार्ड में ४.०२ लाख रूपये की लागत से कन्हैया रस्तोगी के मकान व स्व० राकेश कान्त शुक्ला के मकान के पास की गलियों में सी०सी० सड़क के कार्यों का लोकार्पण किया। इसी प्रकार विधायी एवं न्याय मंत्री ने यहियागंज वार्ड के अन्तर्गत ७.५६ लाख रूपये की लागत से कहोरों का अड्डा में माया के मकान से श्वेता गुप्ता एडवोकेट के मकान तक सड़क एवं नाली, कुण्डरी रकाबगंज वार्ड में ६६ हजार रूपये की लागत से तिकोना पार्क भुइयन देवी मंदिर के पास समरसेबिल पम्प वोरिंग व पानी की टंकी लगाने, इसी वार्ड के अन्तर्गत ६६ हजार रूपये की लागत से कुण्डरी रकाबगंज गढइया पार्क शिव मंदिर के पास समरसेबिल पम्प बोरिंग व पानी की टंकी लगाने एवं इसी वार्ड के अन्तर्गत ६६ हजार रूपये की लागत से कुण्डरी रकाबगंज वार्ड में तिकोना पार्क के पीछे चन्द्र प्रकाश के आवास के पास समरसेबिल पम्प एवं पानी की टंकी लगाने के कार्यो का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजेन्द्र नगर के क्षेत्रीय नागरिकों ने मा० मंत्री जी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए आभार प्रकट किया है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में अधिशासी अभियन्ता नगर निगम श्री पी०के० सिंह, सहायक अभियन्ता श्री सतीश चन्द्र रावत, अवर अभियन्ता श्री किशोरी लाल, क्षेत्रीय पार्षद श्री राजू दीक्षित, स्थानीय जनप्रतिनिधि श्री रमेश तूफानी, श्री दीपक सोनकर, श्री हिमांशु सोनकर, श्री राहुल निगम, मण्डल अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कौटिल्य दूबे, श्रीमती भाग्य लक्ष्मी, श्रीमती बबिता, श्री मनोज वर्मा एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। गंगा कचलाब्रिज बदायूं, बलिया, यमुना नदी, इटावा, औरैया, जालौन, शारदा–नदी पलियाकल खीरी, घाघरा–नदी तुरतीपार बलिया में तथा क्वानों चन्द्रदीपघाट गोण्डा एवं चम्बल नदी में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों में सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन०डी०आर०एफ०,एस० डी०आर० एफ० तथा पी० ए०सी० की कुल ३७ टीमें तैनाती की गयी।

निजी स्कूल फीस मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब!

नयीदिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस में कथित रूप से १५ प्रतिशत की कटौती करने के एकल–न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील पर शुक्रवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ ४५० से अधिक स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल की अपील पर नोटिस जारी किया। एकल न्यायाधीश के आदेश में गैर–सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में लकडाउन समाप्त होने के बाद की अवधि के लिए छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने की अनुमति दी गई थी। एक्शन कमेटी के वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा, ''हमने सोचा था कि हम पूरी तरह से जीत गए हैं।'' उन्होंने अपने अभिवेदन में कहा कि उनकी चुनौती दिल्ली सरकार द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश की गलत व्याख्या किए जाने तक सीमित है। दीवान ने कहा, ''एकल न्यायाधीश और इस अदालत की खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों को निष्प्रभावी करने के लिए एक जुलाई को परिपत्र जारी किया गया था।'' उन्होंने अदालत से एकल न्यायाधीश के आदेश के दायरे को स्पष्ट करने का आग्रह किया। दिल्ली सरकार ने एक जुलाई के परिपत्र में आदेश दिया था कि गैर–सहायता प्राप्त निजी स्कूल १५ प्रतिशत की कटौती के बाद वित्त वर्ष २०२०–२१ में वार्षिक शुल्क लेने करने के हकदार हैं। अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने अपील का विरोध किया और कहा कि चूंकि परिपत्र पहले ही जारी किया जा चुका है, इसलिए समिति को अपील करने के बजाय इसके खिलाफ एक नई याचिका दायर करनी चाहिए। समिति ने अपनी अपील में आरोप लगाया है कि एकल न्यायाधीश के आदेश का इस्तेमाल ट्यूशन फीस में कटौती को लेकर जोर–जबरदस्ती करने

के लिए किया जा रहा है, जो कि दुर्भावनापूर्ण और अवैध है। वकील कमल गुप्ता के माध्यम से दायर अपील में कहा गया है, ''कार्यकारी डीओई (शिक्षा विभाग) ने व्याख्या की आड़ में एक बाध्यकारी न्यायिक निर्णय को निष्प्रभावी करने, उसकी अवहेलना करने और उसे पूरी तरह से दरकिनार करने के लिए एक नया तरीका खोजा है, जिसके तहत वार्षिक और विकास शुल्क के अलावा ट्यूशन फीस में भी १५ प्रतशित की कटौती की जाएगी।'' अपील में कहा गया है कि एकल न्यायाधीश के समक्ष एकमात्र विवाद वार्षिक और विकास शुल्क मदों के संग्रह के संबंध में था और इस प्रकार आदेश के अनुसार, सभी स्कूलों ने शुल्क के इन मदों पर १५ प्रतिशत की कटौती की है। यह दावा किया जाता है कि ट्यूशन फीस में १५ प्रतिशत कटौती पर एकल न्यायाधीश ने कोई निर्णय नहीं दिया था। इस मामले में आगे की सुनवाई २० अगस्त को होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत सात जून को 'एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स' को नोटिस जारी किया था और उससे एकल न्यायाधीश के ३१ मई के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार, छात्रों और एक गैर सरकारी संगठन की अपीलों पर जवाब मांगा था। एकल पीठ ने ३१ मई के अपने आदेश में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा अप्रैल और अगस्त २०२० में जारी दो कार्यालय आदेशों को निरस्त कर दिया था, जो वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने पर रोक लगाते हैं तथा स्थगित करते हैं। अदालत ने कहा था कि वे 'अवैध' हैं और दिल्ली स्कूल शिक्षा (डीएसई) अधिनियम एवं नियमों के तहत शिक्षा निदेशालय को दी गयी शक्तियों से परे हैं। एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास गैर–सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले वार्षिक और विकास शुल्क को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह उनके कामकाज को अनुचित रूप से बाधित करेगा।

अफोर्डेबल हाउसिंग नीति से आवासीय समस्या का होगा समाधान

लखनऊ। समाज के समस्त वर्गों के व्यक्तियों को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नई अफोर्डेबल नीति तैयार की जा रही है, जिसमें पूर्व की नीतियों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का निराकरण किया गया है तथा आवंटियों के हितों को ध्यान में रखा गया है। इस नीति के क्रियान्वयन से आवासीय समस्या के समाधान के साथ–साथ नगरों में अनावश्यक कालोनियों के विकास पर भी नियन्त्रण लगेगा। इस नीति के अन्तर्गत समाज के दुर्बल, अल्प, लघु मध्यम एवं मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार भवन उपलब्ध कराया जायेगा। नगरीय भूमि के इष्टतम उपयोग के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए भू–आच्छादन एफ०ए०आर० एवं डेन्सिटी को बढ़ाया जायेगा। पार्किंग की प्रर्याप्त व्यवस्था होगी। प्रकाश व्यवस्था हेतु अपरम्पारिक उर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित किया जायेगा। ग्रीन बिल्डिंग होने की दशा में अतिरिक्त एफ०ए०आर० दिये जाने का प्राविधान होगा। ई०डब्लू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों के निर्माण में पर्यावरण की दृष्टिकोण से सुस्थिर निर्माण सामाग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। साथ ही प्री फेब्रीकेटेड तकनीक का इसमें उपयोग किया जायेगा। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना– ग्रामीण के तहत समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थित जरूरतमंद लोगों को आवासीय सुविधा का लाभ देते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका खारिज

नागपुर। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जनप्रतिनिधित्व कानून, १९५१ के तहत अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले वकील राम खोबरागडे पर जुर्माना भी लगाया है। याचिका में अनुरोध किया गया था कि मोदी और शाह को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा १२३ के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिया जाए और २०१९ के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श चुनावी आचार संहिता के कथित उल्लंघन

के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की खंडपीठ ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है क्योंकि यह जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा ८०–८१ के अलावा संविधान के अनुच्छेद १०२ में दिए गए प्रावधानों की अनदेखी करते हुए दायर की गई थी। अदालत ने कहा कि एक वकील होने के बावजूद याचिकाकर्ता ने अन्य कानूनी उपायों की मदद लेने के बजाय सीधे उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उसे यह राशि उच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति के पास जमा करानी होगी।

दिल्ली के व्यापारी ने बनाया हवा महल जैसा ढांचा, MCD ने दिया उसे गिराने का आदेश

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध मार्केट चांदनी चौक इस समय आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। बता दें कि दिल्ली के एक व्यापारी ने चांदनी चौक में जयपुर के प्रतिष्ठित हवा महल की तरह दिखने वाली इमारत बनाई है जिसको लेकर अब काफी विरोध जताया जा रहा है। बता दें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इस इमारत को गिराने की चेतावनी दी है। इस इमारत का निर्माण राजस्थान के व्यापारी और वास्तुकार अंकित कील ने किया था लेकिन लोगों और व्यापारियों के विरोध के बाद अब दुकानदार के मालिक को नोटिस भेजा गया है और इमारत की सजावट को हटाने, साथ ही इसे पुराने आकार में वापस लाने को कहा गया। ऐसा नहीं करने पर नर्थ एमएसडी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि, वह कार्रवाई करेगा और पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। बता दें कि नोटिस के बाद से मालिक ने इमारत की सजावट को हटाना शुरू कर दिया है। मालिक ने इस इमारत की मरम्मत के लिए साल २०१९ में अनुमति मांगी थी, जोकि उसे मिली भी लेकिन मालिक ने इमारत के ढांचे में पूरा बदलाव कर दिया और दावा किया कि अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया बल्कि केवल मरम्मत कार्य किया गया था। मालिक ने बताया कि, इमारत की मरम्मत के लिए फाइबर और प्लास्टर अफ पेरिस का उपयोग किया गया था और लाल रंग को चुना गया था ताकि यह पुनर्विकास योजना से मेल खा सके। मालिक के मुताबिक, इमारत का डिजाइन मेहरानगढ़ किले के श्झरोखाश से प्रेरित है। इस इमारत को बनवाने में लगभग २० लाख रुपये का खर्च आया था। जानकारी के लिए बता दें

कि,चांदनी चौक का पूरा इलाका शाहजहांनाबाद विकास मंडल के तहत स्पेशल जोन में आता है। ऐसे में भवनों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी गई है। इमारतों को उनके मूल ढांचे में रखकर ही मरम्मत की जा सकती है। ऐसा इसलिए है ताकि पुरानी दिल्ली क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया जा सके। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा ट्विटर पर इसकी तस्वीर साझा की है।

रेट्रो टैक्स में बदलाव से भारत में निवेश को मिलेगी मजबूती, जानिए इसके बारे में

नई दिल्ली। कई कंपनियों के साथ चल रहे टैक्से विवाद को खत्मव करने के लिए रेट्रो टैक्सा रोलबैक बिल लोकसभा में पेश किया गया। इस संशोधन प्रस्तामव के मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम खत्म होगा। वहीं सरकार पुराने वसूले गए टैक्स वापस कर सकती है, इसमें ब्याज शामिल नहीं होगा। कंपनियों को लिखित में देना होगा कि आगे कोई क्लेम नहीं करेंगी। बता दें कि वोडाफोन, केयर्न सहित कुल १७ केस में ऐसी टैक्सत वसूली को लेकर विवाद था। रेट्रो टैक्स कंपनियों के पूंजीगत लाभ पर कर लगाया कर है, जिससे केयर्न एनर्जी पीएलसी और वोडाफोन समूह जैसी ब्रिटिश फर्मों में गिरावट आई। साल २०१२ में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन ग्रुप के इनकम टैक्स कानून की व्यासख्यान को सही माना था और कहा था कि कंपनी को हिस्से दारी खरीदने पर कोई टैक्सन नहीं देना है। इसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने फाइनेंस बिल में एक संशोधन का प्रस्ता व किया, जिसमें टैक्सव अधिकारियों को इस तरह की डील

पर रेट्रो टैक्सर वसूली का अधिकार दिया गया। भारत सरकार और वोडाफोन के बीच यह मामला तकरीबन २०,००० करोड़ के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर था। केयर्न एनर्जी पीएलसी के शेयर ट्रांसफर को लेकर भी इसी तरह का मामला था। केयर्न ने २००६ में अपनी भारतीय इकाई का बीएसई पर लिस्टक कराया था। पांच साल बाद सरकार ने एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सी कानून पारित किया और केयर्न पर १०,२४७ करोड़ रुपये के ब्याज और जुर्माना लगाया। यह मामला हेग के एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूघ्नल मे गया, जहां दिसंबर २०२० में केयर्न एनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। जानकारों का कहना है कि यह स्वागत योग्य कदम है और इससे अनुकूल निवेश के लिए भारत निवेशकों की पसंद बनेगा। निवेशकों के लिए टैक्स की दरें भी काफी आकर्षक हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश में निवेश के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सरकार ने बड़े सुधार किए हैं। ईवाई के टैक्स पार्टनर प्रणव सयता ने कहा कि यह कर कानूनों में स्पष्टता लाता है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अनावश्यक लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे खत्म होंगे। कंपनियां अब बिना किसी कर लागत या दंड के मामले निपटा सकेंगी।

सीमाओं पर अस्थिर हालात का सामाना करते हुए सेना और मजबूत हुई : जनरल नरवणे

पुणे।थल सेना प्रमुख एम एम नरवणे ने शुक्रवार को कहा कि कोविड–१९ महामारी के दौरान पश्चिम और उत्तर की 'अस्थिर' सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय सेना और मजबूत हुई। जनरल नरवणे ने कहा कि उन्होंने हमेशा कहा है कि युद्ध दो सेनाओं के बीच नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि दो देशों के बीच लड़े जाते हैं। उनकी टिप्पणी ऐसे दिन आयी है जब भारतीय सेना ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गोगरा टकराव बिंदु पर भारत और चीन की सेनाओं ने अपने–अपने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है तथा जमीनी स्थिति को गतिरोध–पूर्व अवधि के समान बहाल कर दिया है।भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के टेलीविजन विंग की स्वर्ण जयंती (१९७१–२०२१) के उद्घाटन समारोह में जनरल नरवणे ने बुनियादी मूल्यों को मजबूत करने, देश की विविध संसेंति को संरक्षित करने और संकट के समय में इसे प्रेरित करने में मुख्यधारा के सिनेमा की भूमिका की सराहना की। हालांकि, थल सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सैन्य बलों के अधिकारियों को एक 'ढर्रे' पर दिखाने से बचना चाहिए। सेना प्रमुख ने कहा, ''हल्के फुल्के अंदाज में कहना चाहूंगा...मैंने हमेशा पाया है कि फिल्मों में भारतीय (सशस्त्र बलों के) अधिकारियों को ढर्रागत तरीके से ही दिखाया जाता है। किसी खूबसूरत नायिका का पिता कोई खडूस कर्नल होता है, जो सिल्क का गाउन पहनता है और एक हाथ में व्हिस्की की बोतल होती है और दूसरे हाथ में बंदूक होती है। यह वाकई में मुझे परेशान

करता है। सृजनात्मक आजादी का मैं सम्मान करता हूं। मुझे लगता है कि घिसे–पिटे तरीके से किसी समुदाय और चरित्र को दिखाने से परहेज करना चाहिए।'' सेना प्रमुख ने कहा कि देश चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, ''महामारी के दौरान पश्चिम और उत्तर दोनों सीमाओं पर (पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं का हवाला देते हुए) अस्थिरता बढ़ गयी। हालांकि, इन चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय सेना और मजबूत हुई।

अदालत ने हत्या मामले में पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान लिया, २० अगस्त को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और उसके १२ अन्य साथियों के खिलाफ सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आरोपपत्र का शुक्रवार को संज्ञान लिया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) सतवीर सिंह लांबा ने आरोपपत्र का संज्ञान लिया और सभी आरोपियों को अंतिम रिपोर्ट की प्रतियां सौंपने के लिए मामले की सुनवाई २० अगस्त के लिए निर्धारित की। धनखड़ और उसके चार दोस्तों के साथ संपत्ति विवाद को लेकर चार और पांच मई की दरम्यानी रात को स्टेडियम में कुमार और अन्य ने कथित तौर पर मारपीट की थी।बाद में, जख्मों के कारण सागर की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या के इस मामले

में तीन अगस्त को आरोपपत्र दायर किया था जिसमें कुमार को मुख्य आरोपी नामजद किया गया है। आरोपपत्र में, पुलिस ने सागर का मौत के वक्त दिया बयान, आरोपी की मौजूदगी वाली जगह, सीसीटीवी फुटेज और मौके से बरामद वाहनों समेत वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया है। भारतीय दंड संहिता के तहत हत्यासमेत २२ अपराधों के लिएमुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए इसमें कहा गया, "जांच के दौरान अब तक एकत्र की गई सामग्रियों जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, उससे सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं।" आरोप–पत्र में अभियोजन पक्ष के १५५ गवाहों के नाम का उल्लेख है, जिनमें वे चार लोग भी शामिल हैं जो इस विवाद के दौरान घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, दंगा जैसे अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।

जम्मू–कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर होंगे राहुल गांधी, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार से दो दिनों के जम्मू–कश्मीर दौरे पर होंगे जिस दौरान वहप्रदेश कांग्रेस

कमेटी के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राहुल गांधी नौ अगस्त को श्रीनगर पहुंच सकते हैं और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के पुत्र की शादी में भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि वह इस केंद्र शासित प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे।

समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ही जनता का दुख–दर्द दूर होगा : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि जब से भाजपा सत्ता में आई तब से जनता को महंगाई और अपराध के दर्द से रोज गुजरना पड़ रहा है, लेकिन सपा की सरकार बनने पर जनता का दुख दर्द दूर होगा। शुक्रवार को सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार जबसे सत्ता में आई है, तबसे राजनीति में घोर गिरावट नजर आई है, उत्तर प्रदेश में वैचारिक प्रदूषण भी खूब बढ़ा है, जनता के कष्टों का निवारण तो हुआ नहीं उल्टे उसको मंहगाई और अपराध के दर्द से रोज ही गुजरना पड़ रहा है, समाजवादी सरकार बनने पर ही जनता के दुःख दर्द दूर हो सकेंगे। यादव ने आरोप लगाया, भाजपा राज में जनसामान्य की कहीं सुनवाई नहीं है, सत्ता के संरक्षण में अपराध, लूट और अपहरण की घटनाएं रूकने का नाम नहीं ले रही

हैं, मुख्यमंत्री जी का जीरो टलरेंस का दावा बस दावा ही बनकर रह गया है और लगता ही नहीं है कि भाजपा सरकार का सच्चाई से भी कोई रिश्ता है। उन्होंने कहा, जनता जिस पीड़ा से गुजर रही है उसकी तनिक भी अनुभूति न होना भाजपा सरकार और इसके नेतृत्व की संवेदनशून्यता का परिचायक है। यादव ने कहा, जगह–जगह मुफ्त राशन बांटने के लिए मोदी जी को धन्यवाद देने वाले मुख्यमंत्री को यह नहीं दिखाई देता है कि जनता को राशन मिलने में कितनी कठिनाई हो रही है। कोटेदार घटतौली के सहारे गरीबों का राशन लूट रहे हैं। लाभार्थियों को कम राशन देने पर आपत्ति की गई तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सपा प्रमुख ने कहा, गरीबों के राशन के साथ भाजपा राज में घरेलू अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई है, महिलाओं का घर चलाना दुश्वार हो गया है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और रसोई गैस के दामों में तेजी से वृद्धि होने से मध्यम आय वर्ग के लोगों की भी कमर टूट गई हैं।

भारत में है अद्भुत कुंड : भीम कुण्ड, रहस्यों से भरा, वैज्ञानिक भी फेल

अमरेन्द्र सहाय अमर

दुनिया में आज भी ऐसे कई रहस्य हैं, जो अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं, क्योंकि उनके बारे में पता लगाने में वैज्ञानिक भी फेल हो गए हैं. आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भारत में है और इसके बारे में कहा जाता है कि कुंड की गहराई का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं. मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा तहसील से मात्र १० किलोमीटर की दूरी पर स्थित

है प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्भीमकुंडश. मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित यह स्थान प्राचीनकाल से ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं साधकों की स्थली रही है. वर्तमान समय में यह स्थान धार्मिक पर्यटन एवं वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बन हुआ है. यहां स्थित जल कुंड भू–वैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय है, दरअसल, यह कुंड अपने भीतर अतल गहराइयों को समेटे हुए हैं. आश्चर्य की बात है कि वैज्ञानिक इस जल कुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, किंतु इस जल कुंड की गहराई की थाह अभी तक कोई नहीं पा सका. ऐसी मान्यता है कि १८ वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिजावर रियासत के महाराज ने यहां पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन करवाया था. उस मेले की परंपरा आज भी कायम है. मेले में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं. भीम कुंड एक गुफा में स्थित है. जब आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं, तो यहां पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थ र दिखाई देते हैं. यहां लाइट भी कम होती है, लेकिन यहां का नजारा हर किसी का मन मोह लेता है. भीम कुंड के ठीक ऊपर बड़ा–सा कटाव है, जिससे सूर्य की किरणें जब कुंड के पानी पर पड़ती हैं. सूर्य की किरणों से इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभर आते हैं. यह भी कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय पश्चात खुद–ब–खुद ऊपर आ जाता है. इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अश्य हो जाता है. भीम कुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर चतुर्भुज विष्णु तथा लक्ष्मी का विशाल मंदिर बना हुआ है. विष्णु–लक्ष्मीजी के मंदिर के समीप एक और प्राचीन मंदिर स्थित है. इसके ठीक विपरीत दिशा में एक पंक्ति में छोटे–छोटे तीन मंदिर बने हुए हैं, जिनमें क्रमशरू लक्ष्मी–नृसिंह, राम दरबार और राधा–ेष्ण के मंदिर हैं. भीम कुंड एक ऐसा तीर्थ स्थल है, जो व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों के आनंद की अनुभूति कराता है. भीमकुंड से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं. ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तब वे यहां के घने जंगलों से गुजर रहे थे. उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी. लेकिन, यहां पानी का कोई स्रोत नहीं था. द्रौपदी व्याकुलता देख गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपने गदा से पहाड़ पर प्रहार किया. इससे यहां एक पानी का कुंड निर्मित हो गया. कुंड के जल से पांडवों और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम पर ही इस का नाम भीम कुंड पड़ गया. इसके अलावा इस कुंड को नील कुंड या नारद कुण्ड के नाम से भी जाना जाता है. बताते हैं कि एक समय नारदजी आकाश से गुजर रहे थे, उसी समय उन्हें एक महिला और पुरुष घायल अवस्था में दिखाई दिए. उन्होंने वहां आकर उनकी इस अवस्था का कारण पूछा तब उन्होंने बताया कि वे संगीत के राग–रागिनी हैं. वे तभी सही हो सकते हैं, जब कोई संगीत में निपुण व्यक्ति उनके लिए सामगान गाए. नारदजी संगीत में पारंगत थे. उन्होंने उसी समय सामगान गाया जिसे सुनकर सारे देवतागण झूमने लगे. विष्णु भगवान भी सामगान सुनकर खुश हो गए और एक जल कुंड में परिवर्तित हो गए. उनके रंग के जैसे ही इस कुंड का जल नीला हुआ तभी से इसे नीलकुंड भी कहा जाने लगा. कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके पता लगाने की कोशिश की कि इसका जल इतना साफ और स्वच्छ कैसे है? और इसकी गहराई भी जानना चाही लेकिन आज तक कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया है. एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए थे तो उन्होंने बताया था कि अंदर दो कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं. एक से पानी आता है और दूसरे से वापस जाता है और उसकी स्पीड भी बहुत तेज है. स्थानीय लोगों के अनुसार इसका संबंध सीधे समुद्र से है, क्योंकि इस कुंड के एक तरफ से जहां जाली नहीं लगी हुई है, वहां से जो भी लोग इसमें डूबे हैं उनकी लाश तक नहीं मिली है. इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आई थी तब इस कुंड में भी हलचल हुई थी. इसके पानी की लहरें १० फुट तक उठ रही थीं. उस समय यहां मौजूद सारे के सारे लोग डरकर बाहर निकल गए थे. इसका जल हमेशा साफ और स्वच्छ रहता है. इसमें काफी गहराई तक की चीजें साफ दिखती हैं और जब सूर्य की रोशनी इस कुंड पर आती है तब बहुत ही मनमोहक श्य दिखता है. इसके अलावा एक रहस्य यह भी है कि इस कुंड का जलस्तर कभी कम नहीं होता. यहां पर बने आश्रम जहां बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं और आसपास के सारे क्षेत्र में यहीं से पानी की सप्लाई होती है. लेकिन पानी खत्म होना तो दूर, गर्मियों के समय में भी यहां का जलस्तर कभी कम नहीं होता है. एक बार तो सरकार की ओर से भी इसका तल जानने के लिए वटर पंप से यहां के पानी को निकाला गया था, तब भी यहां का स्तर कम नहीं हुआ।

सरकार की दलील पर हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

लखनऊ, । इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राज्य सरकार ने कहा कि यदि इस बात पर सुरक्षा मांगी जानी लगेगी कि याची किसी अदालत में फौजदारी की वकालत करता है या जनहित याचिकायें दाखिल करता है तो फिर तो ऐसे सभी वकीलों को सुरक्षा देनी पड़ेगी। यह कहकर सरकार ने लखनऊ खंडपीठ में वकालत करने वाले एक अधिवक्ता द्वारा सरकारी खर्चे पर सुरक्षा प्रदान करने की मांग का जोरदार विरोध किया। इस पर हाईकोर्ट ने न केवल वकील की याचिका खारिज कर दी अपितु सरकार को कई दिशा निर्देश देकर कहा कि वह सरकारी सुरक्षा देते समय उनका पालन सुनिश्चित करे। जस्टिस रितुराज अवस्थी व जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सुरक्षा केवल वीवीआईपी स्टेटस के लिए नहीं दी सकती। इसके लिए खतरा वास्तविक होना चाहिए और यह जानने के लिए सुरक्षा समिति को इंटेलिजेंस यूनिट व संबधित पुलिस की रिपोर्ट व व्यक्ति का इतिहास जरूर देखना चाहिए।याची अधिवक्ता अभिषेक तिवारी ने याचिका दायर कर अप्रैल २०२१ में पारित सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उच्च स्तरीय समिति के

सुझाव के आधार पर उसकी अंतरिम सुरक्षा खत्म कर दी गयी थी। उसकी ओर से तर्क था कि वह हाई कोर्ट में फौजदारी की वकालत करता है तथा जनहित याचिकायें दाखिल करता है अतरू उसकी जान को खतरा रहता है और इसीलिए उसे सरकारी सुरक्षा प्रदान की जाए।याचिका का विरोध ा करते हुए सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमिताभ राय का तर्क था कि याची के तर्क का मानने का अर्थ है कि सभी फौजदारी के अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए जो कि संभव नहीं है। कहा कि याची ने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया जिससे लगे कि उसे जान का खतरा है। कहा कि याची का वाघ्षक टैक्स रिटर्न चार लाख ५० हजार रुपये है। उसे पहले १० प्रतिशत खर्चे पर जौनपुर से एक गनर मिला हुआ था। अब उसे लखनऊ से एक गनर चाहिए जबकि उसे कोई खतरा नहीं होने की रिपोर्ट है।याचिका को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति से आपसी दुश्मनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई पैमाना नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट व्यक्ति को सरकारी सुरक्षा नहीं देनी चाहिए जब तक कि कोई अति महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं हो। सरकार को ऐसे लोगो को सुरक्षा प्रदान कर उनका कोई विशिष्ट वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह कहते हुए कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को आदेश दिया कि इस फैसले की प्रति मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह व डीजीपी को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाए।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में दुष्कर्म-हत्या मामले में जताया दुख

लखनऊ। दिल्ली के कैंट इलाके में ६ साल की मासूम के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला गरमा गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्ययक्ष मायावती ने दिल्ली कैंट के नांगल गांव में एक नौ वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि घटना अति दुखद और शर्मनाक है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबार न हों।बसपा प्रमुख मायावती ने बुध ावार को ट्वीट कर कहा कि शदिल्ली कैंट के नागल गांव में नौ वर्षीय दलित लड़की की दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या व फिर उसके शव को जला देने की घटना अति दुखद और शर्मनाक है। दोषियों के विरुद्ध अविलंब सख्त कार्रवाई करने व ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की बीएसपी की मांग।शबता दें कि रविवार को दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। आरोप है कि बच्ची से श्मशान घाट के अंदर दुष्कर्म कर उसकी हत्या करके शव जला दिया गया। इस मामले में शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही से मौत, सबूत मिटाने और परिवारीजन को बिना बताए शव का अंतिम संस्कार करने जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, पॉक्सो, एससी–एसटी एक्ट और जान से मारने की धमकी देने समेत कई अन्य धाराएं भी जोड़ दीं। इस मामले में श्मशान घाट के

पुजारी समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि बच्ची के शरीर के बचे हुए अंगों का पोस्टमार्टम कराया गया है। डक्टरों के बोर्ड ने बताया है कि शरीर केघ जितने अंग हैं उनसे मौत के कारण का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अवशेषों को हम परिवार को सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति जरूरी होती है। अगर आरोपी मान जाते हैं तो हम लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट करेंगे। हम लोग आरोपियों को न्यायिक हिरासत से रिमांड में लाएंगे और पूछताछ करेंगे।

पत्नी का गला रेतकर फरार

लखनऊ। पारा के मुन्नूखेड़ा गोकुलग्राम आवास विकास कालोनी के तीसरी मंजिल पर पति ने पत्नी की धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और मकान का दरवाजा बंदकर फरार हो गया। बुधवार सुबह नवविवाहिता का भाई, बहन का हालचाल लेने के लिए आया था। लेकिन दरवाजा लक था। भाई ने बहन को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो भाई ने दरवाजे के नीचे की झीरी से झांक कर देखा तो उसकी बहन पैर दिखाई दे रहा था। जिस पर भाई ने ११२ पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। तो देखा कि नवविवाहित का खून से लथपथ शव अन्दर कमरे की फर्श पर पड़ा हुआ था और मौके से सफेद रंग की खून से सनी शर्ट व आला कत्ल खून से सना चाकू भी बरामद किया।उन्नाव अचलगंज नेवरना निवासी श्रींष्ण की २६ वर्षीय बेटी लकी रावत उर्फ दीपिका ने बीते ३१ मई २०२१ को ठाकुरगंज रमना रिंगरोड फरीदीपुर सुन्दरनगर निवासी रामसनेही यादव के बेटे दुर्गेश यादव उर्फ अभिषेक के साथ प्रेम विवाह किया था और शादी में दीपिका की मां श्यामा उर्फ कमला देवी शामिल हुई थी। शादी के बाद से लकी उर्फ दीपिका अपने प्रेमी पति दुर्गेश के साथ मुन्नूखेड़ा गोकुलग्राम आवास कालोनी के २८ नम्बर ब्लाक की तीसरी मंजिल में पिछले दो माह से किराए पर रह रही थी। दीपिका पीजीआई में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। नवविवाहिता लकी उर्फ दीपिका के भाई बच्चूलाल ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से दुर्गेश व उसकी मां पिता रामसनेही और भाई दहेज के प्रताड़ित कर मारपीट करते थे। बहन दीपिका बीते २ अगस्त को मायके गई थी और

बहन को सोने की जंजीर व झाले देकर और लकेट लेकर ससुराल आई थी। जहां ससुरालीजनों ने मिलकर दीपिका की पिटाई कर दी थी। जिस पर दीपिका ने टेम्पो चालक के फोन से घर पर फोन कर घटना की जानकारी दी थी। जिस पर भाई बच्चूलाल ३ अगस्त को बहन दीपिका का हाल चाल लेने के लिए मुन्नूखेड़ा आवास पर आया था। लेकिन दरवाजा बंद था। बच्चूलाल ने बताया कि वो निचले तल पर पेड़ के नीचे बैठा रहा।आज सुबह दोबारा दरवाजा खटखटाकर आवाज दी। लेकिन घर से कोई जवाब नहीं मिला। जिस पर दरवाजे के नीचे से झीरी से झांककर देखा तो बहन दीपिका का पैर जमीन पर दिखाई दिया। जिस पर घटना की जानकारी ११२ पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पारा पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो लकी उर्फ दीपिका का शव अन्दर कमरे में खून से लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ था। दीपिका का गला धारदार चाकू से रेता गया था। तो वहीं उसके हाथ में चाकू के वार थे। घटना की जानकारी होते ही मौके पर एडीसीपी दक्षिणी पुणेन्द्र सिंह एसीपी काकोरी आसुतोष कुमार पारा इंस्पेक्टर राजेश कुमार व फारेंसिक टीम मौके पर पहुॅचकर छानबीन में जुट गए। घटना को लेकर मृतक लकी उर्फ दीपिका के भाई बच्चूलाल ने प्रेमी पति दुर्गेश यादव उर्फ अभिषेक व उसके पिता रामसेनही और मॉ व भाई के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाकर पारा थाना में तहरीर दी है।

मुख्तार अंसारी की पत्नी का फ्लैट सीज

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पुलिस माफियाओं के खिलाफ लगातार लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को गाजीपुर जिले की पुलिस ने महानगर में पेपर मिल कलोनी स्थित मुख्तार की पत्नी अफशां के नाम दर्ज फ्लैट की कुर्की की। यह कार्यवाही गैंगेस्टर एक्ट में की गई है। गाजीपुर जिले की पुलिस ने कुर्की से पहले की नोटिस कुछ दिन पहले चस्पा की थी। गाजीपुर जिले में अफशां अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआइआर पंजींत है। इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। अफशां अंसारी के नाम

पर लिए गए शस्त्र के क्रय विक्रय में अनियमितता पाई गई थी।शासन के आदेश पर छानबीन की गई तो आरोप सही पाए गए। इसके बाद अफशां अंसारी को बयां दर्ज करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस को सहयोग नहीं किया। जून २०२० में गाजीपुर पुलिस ने पेपर मिल कलोनी स्थित फ्लैट पर नोटिस चस्पा कर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। बावजूद इसके अफशां अंसारी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। अफशां फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। हजरतगंज कोतवाली में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी व अन्य के खिलाफ जालसाजी की एफआइआर दर्ज है। हाल में ही गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार के साले के खिलाफ भी कार्यवाही की थी और उसकी संपत्ति जब्त की गई थी। बुधवार शाम करीब पांच बजे गाजीपुर पुलिस महानगर के अतिरिक्त इंस्पेक्टर ओमप्रकाश सिंह व पुलिस बल के साथ पेपर मिल कालोनी मेट्रो सिटी के टावर नंबर २० पहुंची।यहां १०वें तल पर स्थित मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां का फ्लैट सीज कर दिया गया। इस दौरान पहले पुलिस टीम ने लाउडीस्पीकर से एनाउंस किया। इसके बाद डुग्गी पिटवाई गई और फिर कार्यवाही हुई। इस दौरान सदर तहसील के तहसीलदार ज्ञानेंद्र व अन्य लोग भी मौजूद रहें। कुर्की के दौरान फ्लैट में कोई नहीं मिला। मुख्तार के पक्ष के अधिवक्ता फ्लैट की चाभी देने आए थे, जिनके सामने कुर्की की कार्यवाही की गई। फ्लैट की कीमत करीब १.१८ करोड़ रुपये है। डालीबाग स्थित टावरों का हुआ था ध्वस्तीकरण रू प्रशासन की ओर से मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम से जो दो टावर डालीबाग में थे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यवाही के तहत उनका पूर्व में ही ध्वस्तीकरण किया था। वहीं, गाजीपुर जिले के सैयदाबाड़ा स्थित आवास को भी कुर्क करके प्रशासन ने जब्त कर लिया था।

आगामी विस चुनाव की तैयारियों को लेकर केन्ट विधानसभा में भाजपा ने मण्डल कार्यसमिति बैठक का हुआ आयोजन

लखनऊ। आलमबाग कैण्ट विधानसभा क्षेत्र के सिंगार नगर बारात घर में शुक्रवार को भाजपा

पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मण्डल कार्यसमिति बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से कैण्ट विधानसभा के विधायक सुरेश चन्द्र तिवारी महानगर कैंट मंडल –कार्यसमिति बैठक क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिव भूषण मुख्य वक्ता द्वितीय सत्र राकेश श्रीवास्तव (राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं बैठक प्रदेश संयोजक), महापौर संयुक्ता भाटिया मंडल प्रभारी आलोक सिंह मंचासीन रहे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर मण्डल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर प्रधानमंत्री के संदेश व उनकी योजनाओं को घर घर पहुंचाने व जागरूक करने की बात कहा । इस बैठक की अध्यक्षता सचिन वैश्य (मण्डल अध्यक्ष) महामंत्री अंकित मिश्रा ने किया। इस दौरान पार्षदगण, मोर्चों के अध्यक्ष व महामंत्री व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

इंस्पेक्टर कृष्णानगर समेत दो दारोगा लाइन हाजिर

लखनऊ। बाराबिरवा चौराहे पर कैब चालक सआदत की पिटाई के मामले में लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टरें ष्णानगर समेत दो दारोगा को लाइन हाजिर कर दघ्या गया है। एसीपी की जांच में सामने आया था कि दारोगा मन्नान और हरेंद्र सिंह ने ड्यूटी पर लापरवाही बरती थी। जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है।सआदत ने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पूरी कहानी बयां की है। कैब चालक ने अधिकारियों को बताया है कि शुक्रवार रात में ड्यूटी पर मौजूद दारोगा मन्नान ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था। यही नहीं कोतवाली पहुँचे सआदत के भाइयों से भी दारोगा ने अभद्रता की थी और उन्हें लकअप में डाल दिया था। एसीपी ष्णानगर और एडीसीपी मध्य चिरंजीव नाथ सिन्हा ने पीड़ित के बयान के आधार पर जांच की है। बुधवार रात लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। सूत्रों का कहना है कि एसीपी और एडीसीपी की जांच रिपोर्ट में इंस्पेक्टरें ष्णानगर महेश दुबे की लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस अधिकारियों ने इंस्पेक्टर से पूरे मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा है।उधर, कैब चालक की पिटाई करने की आरोपित प्रियदर्शिनी नारायन उर्फ लक्ष्मी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रियदर्शिनी ने खुद को बेकसूर बताया है। प्रियदर्शिनी पर दर्ज एफआइआर की विवेचना इंस्पेक्टर बंथरा कर रहे हैं। इंस्पेक्टर बंथरा का कहना है कि कैब चालक को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आए। चालक के अधिवक्ता ने वादी के थाने जाने में असमर्थता जताई। चालक का बयान दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

केसरी खेड़ा रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप

लखनऊ। कृष्णा नगर कोतवाली इलाके स्थित केसरी खेड़ा रेलवे क्रासिंग के निकट रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक की शिनाख्त हो जाने पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों के मुताबिक मृतक पिछले करीब दो वर्षों से कैंसर रोग से पीड़ित था। कृष्णा नगर कोतवाली प्रभारी आलोक राय ने मृतक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र स्थित केसरी खेड़ा क्रासिंग के रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार सुबह एक अधेड़ का शव क्षत–विक्षत अवस्था में पड़ा मिला है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव का शिनाख्त करा पहचान हो जाने पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त मूल रूप से मालदा टाउन पशिचम बंगाल का रहने वाला रमन सरकार (४०) पुत्र शंकर सरकार के रूप में हुआ है। वर्तमान में मृतक अपनी पत्नी शिल्पी व चार पुत्रियों संग कृष्णा नगर इलाके स्थित अम्बेडकर नगर में रहता था। वहीं मृतक की पत्नी के मुताबिक मृतक विगत दो वर्षों से कैंसर की बीमारी से ग्रसित था। जिसका इलाज मेडिकल कलेज अस्पताल में चल रहा था। मृतक बीते गुरुवार की शाम घर से बिना बताए चला गया था। जिसकी जानकारी उसने स्थानीय पुलिस को दी थी। वहीं शुक्रवार सुबह पुलिस द्वारा पति के मौत की जानकारी मिली है।

फिल्म मेकर विभु अग्रवाल पर लगा यौन शोषण का आरोप, मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तारी के बाद अब इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल, फिल्म मेकर विभु अग्रवाल पर यौन शोषण के आरोप में मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। विभु अग्रवाल पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। फिल्म मेकर के साथ ही उनकी कंपनी उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड की कंट्री हेड अंजलि रैना पर भी एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। बता दें कि यह कंपनी एडल्ट फिल्में बनाने के लिए जानी जाती है। मुंबई पुलिस ने विभु अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा ३५४ के तहत मामला दर्ज किया है। विभु अग्रवाल ने साल २०१६ में उल्लू ऐप लॉन्च किया था और साल २०१३ में फिल्म बात बन गई प्रोड्यूस की थी। विभू चोपड़ा के उल्लू ऐप कई अलग–अलग भाषाओं में एडल्ट फिल्में मौजूद थी। आपको बता दें कि पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा पहले से ही जेल में है। ऐसे में अब विभु अग्रवाल का नाम भी कुछ इसी तरह के मामले में सामने आना फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।

शाहरुख खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार सहित तमाम बॉलीवुड सितारो ने पुरुष हॉकी टीम को दी बधाई

मुंबई। अभिनेता शाहरुख खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, तापसी पन्नू सहित कई सितारों ने तोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बृहस्पतिवार को बधाई दी। गौरतलब है कि भारतीय पुरुष

हॉकी टीम ने बृहस्पतिवार को तोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के 'प्ले ऑफ मैच' में जर्मनी को ५–४ से हरा कर ४१ साल बाद ओलंपिक पदक जीतते हुए इतिहास के पन्नों में एक बार फिर अपना नाम दर्ज करा लिया। शाहरुख खान ने टीम का बधाई देते हुए कहा, '' वाह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, शुभकामनाएं। दृढ़ चरित्र एंव कौशल का प्रदर्शन अपने उच्चतम पर। क्या रोमांचक मैच था।'' अभिनेता अनिल कपूर ने भी टीम को बधाई दी और अपने दिवंगत पिता एवं निर्माता सुरेंद्र कपूर को याद किया। उन्होंने कहा, '' अद्भुत जीत.... काश मेरे पिता इस एतिहासिक दिन को देखने के लिए जिंदा होते... हॉकी पुरुष टीम आपका बहुत–बहुत शुक्रिया। बधाई।'' अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, '' दोबारा इतिहास रचने के लिए भारतीय टीम को बधाई। ४१ साल बाद ओलंपिक पदक जीता। क्या मैच था, क्या वापसी की। रुटोक्यो२०२०।'' तापसी पन्नू ने भी टीम की जीत की एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, '' कांस्य पद जीत लिया है।'' अभिनेता राहुल बोस ने भी इंस्टाग्राम पर भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, '' भारत....अद्भुत... पुरुष हॉकी टीम... ओलंपिक कांस्य.. बधाई हो। ओडिशा खेल विभाग समर्थन और विश्वास जताने के लिए शुक्रिया।'' इनके अलावा, अदाकारा तमन्ना भाटिया, अमायरा दस्तूर, दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता निविन पॉली, फिल्मकार मधुर भंडारकर ने भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178

Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक